

डिजिटल रुपये से आप क्या समझते हैं? इस सन्दर्भ में, भारत के केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सी बी डी सी) की कार्यप्रणाली तथा प्रगति का वर्णन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) [UPSC 2026 GS3 ECONOMY]

What do you mean by Digital Rupee? In this context, explain the working and progress of India's Central Bank Digital Currency (CBDC). (Answer in 150 words) 10

डिजिटल रुपया (e₹), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई भारत की आधिकारिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) है। यह भौतिक मुद्रा (बैंक नोट और सिक्कों) का एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसे आरबीआई अधिनियम, 1934 (2022 में संशोधित) के तहत वैधानिक संप्रभु गारंटी और कानूनी निविदा (Legal Tender) का दर्जा प्राप्त है। डिजिटल रुपया बैंकों के देनदारियों का हिस्सा न होकर सीधे केंद्रीय बैंक की देनदारी होता है। इसे नकदी में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1:1 के अनुपात में बदला जा सकता है।

डिजिटल रुपये की कार्यप्रणाली

1. द्वि-स्तरीय मॉडल:

- **पहला स्तर:** आरबीआई डिजिटल टोकन का निर्माण और थोक आवंटन वाणिज्यिक बैंकों को करता है।
- **दूसरा स्तर:** बैंक और गैर-बैंकिंग भुगतान ऑपरेटर उपयोगकर्ताओं (नागरिकों और व्यापारियों) को डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹ वितरित करते हैं।

उदाहरण: अक्टूबर 2025 तक खुदरा पायलट चरण में 19 प्रमुख वाणिज्यिक बैंक शामिल होकर ग्राहकों को e₹ वॉलेट सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

2. टोकन-आधारित स्वामित्व:

- बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय निपटान के विपरीत, e₹ क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डिजिटल टोकन के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ता अपने विशिष्ट डिजिटल वॉलेट में रखे टोकन के स्वामित्व को प्रमाणित करके सीधा हस्तांतरण करते हैं।

3. प्रोग्रामेबिलिटी:

- आरबीआई इसमें विशिष्ट उपयोग की शर्तें कोड कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दी गई राशि का उपयोग केवल तय उद्देश्य के लिए ही हो।

उदाहरण: फरवरी 2026 में गुजरात में शुरू की गई 'CBDC-आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान विशिष्ट डिजिटल टोकन के रूप में किया गया, जिसे केवल पंजीकृत राशन दुकानों पर खाद्यान्न खरीदने के लिए ही भुनाया जा सकता है।

4. तत्काल और अंतिम निपटान:

- इसमें किसी मध्यस्थ या इंटरबैंक क्लियरिंगहाउस (जैसे NPCI) की आवश्यकता नहीं होती। लेन-देन होते ही धन का निपटान अंतिम मान लिया जाता है, जिससे निपटान जोखिम समाप्त हो जाता है।

5. ऑफलाइन लेनदेन क्षमता:

- बिना इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों (दूरदराज या ग्रामीण इलाकों) में नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तथा एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल के माध्यम से दो वॉलेट्स के बीच प्रत्यक्ष लेन-देन संभव है।

6. थोक और खुदरा विभाजन:

- e₹-W (Wholesale):** अंतर-बैंक वित्तीय निपटान और सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार जोखिम को कम करने हेतु।
- e₹-R (Retail):** आम नागरिकों, सूक्ष्म कारोबारियों और दैनिक वित्तीय लेन-देन हेतु।



भारत में CBDC की प्रगति और वर्तमान स्थिति

- उपयोगकर्ताओं का विस्तार:** अक्टूबर 2025 तक रिटेल पायलट प्रोजेक्ट में 70 लाख से अधिक ग्राहक और व्यापारी शामिल हो चुके हैं।
- चलन में मुद्रा की मात्रा:** आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, मार्च 2026 तक भारत में e₹-Retail का कुल चलन ₹771.66 करोड़ तक पहुँच गया।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में उपयोग:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में कल्याणकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे e₹-वॉलेट में ट्रांसफर करने के सफल पायलट परीक्षण आयोजित किए गए।
- गैर-बैंकिंग फिनटेक कंपनियों का एकीकरण:** आरबीआई ने डिजिटल रुपये की पहुँच बढ़ाने के लिए तीसरे पक्ष के फिनटेक ऑपरेटरों (जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm) को भी e₹ वॉलेट सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है।
- सीमा पार भुगतान:**
 - भारत ने सिंगापुर के PayNow नेटवर्क के साथ CBDC इंटरऑपरेबिलिटी पर समझौता किया है।
 - संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ व्यापारिक भुगतान को सरल बनाने और प्रेषण लागत को कम करने के लिए द्विपक्षीय CBDC कॉरिडोर का परीक्षण चल रहा है।

रणनीतिक एवं आर्थिक महत्व

- **कैश हैंडलिंग लागत में कमी:** भौतिक नोटों की छपाई, भंडारण, सुरक्षा और परिवहन पर होने वाले भारी-भरकम वार्षिक खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- **वित्तीय समावेशन:** बिना बैंक खाते या कमजोर इंटरनेट नेटवर्क वाले दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिक भी ऑफलाइन e₹ वॉलेट के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेंगे।
- **मौद्रिक पारदर्शिता और काले धन पर रोक:** प्रत्येक डिजिटल टोकन में ट्रेसबिलिटी होने के कारण यह जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और समानांतर अर्थव्यवस्था (ब्लैक मनी) पर अंकुश लगाता है।
- **डॉलर पर निर्भरता कम होना:** जी-20 क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स रोडमैप और राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय CBDC व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को संतुलित करने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

- **बैंकों की मध्यस्थता में कमी:** बैंकों से जमा राशि e₹ वॉलेट में स्थानांतरित होने पर बैंकों का जमा आधार घटेगा, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता प्रभावित होगी।
- **UPI से प्रतिस्पर्धा:** UPI की व्यापक उपयोगिता और सहजता के कारण आम नागरिकों के बीच e₹ को अपनाने की गति धीमी है।
- **साइबर सुरक्षा व डेटा जोखिम:** डिजिटल वॉलेट पर साइबर हमलों, फिशिंग तथा डेटा हैकिंग का निरंतर जोखिम।
- **ऑफलाइन दोहरे खर्च की समस्या:** इंटरनेट के बिना NFC आधारित लेनदेन में एक ही टोकन को दो बार खर्च होने से रोकना तकनीकी रूप से जटिल है।
- **निजता बनाम पारदर्शिता:** भौतिक नकदी की तरह पूर्ण गुमनामी न होने से आम उपयोगकर्ताओं में वित्तीय निजता (Privacy) को लेकर चिंताएं हैं।

आगे की राह



- **पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability):** UPI QR कोड और बैंकिंग ऐप्स के साथ e₹ का सहज एकीकरण, ताकि एक ही इंटरफेस से लेनदेन संभव हो।
- **प्रोग्रामेबल e₹ से लक्षित कल्याण:** DBT, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं (PDS) में e₹ का उपयोग कर 'लीकेज' और भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
- **डिजिटल साक्षरता व जागरूकता:** नागरिकों और सूक्ष्म कारोबारियों को इसके संप्रभु और ऑफलाइन फायदों के प्रति जागरूक करना।

निष्कर्ष

डिजिटल रुपया भारत को 'कैश-लाइट' और 'डिजिटल-फर्स्ट' अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। सुरक्षात्मक तकनीकों के विकास, UPI के साथ समन्वय तथा प्रभावी नीतिगत ढाँचे के माध्यम से भारत वैश्विक डिजिटल मौद्रिक प्रणाली का नेतृत्व कर सकता है।

JOIN US-RESULT MITRA



